(c) Does not arise in view of reply to parts (a) and (b) above.

Complication of Gel Church Issue

2808. SHRI KAILASH PATI MISHRA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem which appeared in 'Times of India' Delhi Edn. dated 9th October, 1988 under the caption 'PM's letter complicates Gel Church Issue"; if so, whether actually such a letter has been written to Dy. Commissionor of Ranchi;

(b) what are the details thereof; and

(c) whether Government are intending to amend the Urban Ceiling Act only to favour one community?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) P.M. had not written any letter to Deputy Commissioner, Ranchi on Gel Church Issue.

(b) Does not arise.

(c) The question of amending the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 is being examined in consultation with the State Governments/Union Territories with a view to achieving the principal objectives of the enactment.

Irregularities in Birla Provident Fund Trust

2809. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

SHRI RAM NARESH YADAV:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem appearing in the 'Indian Express' dated the 28th October, 1988 under the heading "Irregularities in Birla Provident Fund Trust";

(b) if so, what are the facts thereof;

(c) whether any inquiry has since been conducted; and

(d) the action taken by Government against the Trust for committing irregularities?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A central Inspection team of the EPF Organisation had carried out an inspection of common provident funds of M/s Birla Group of Industries and detected various irregularities in functioning of the Fund.

(d) The Regional Provident Fund Commissioner, Calcutta has been instructed to issue show cause notice and to file prosecution cases against the management under section 14(2A) of the EPF Act if they do not rectify all the irregularities within a reasonable time.

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में किया गया विश्लेषण

2810. श्री राम नरेश यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान न्यूट्रीशन फाउण्डेशन आफ इंडिया द्वारा हाल ही में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में किए गए एक विश्लेषण की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त विश्लेषण के प्रतिवेदन में यह स्वीकार किया गया है कि इस संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने

के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से कोई सफलता नहीं मिली है ;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या भविष्य में सरकार अपनी वर्तमान कार्य योजना में कुछ परिवर्तन करने के बारे में विचार रखेगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां ।

(ख) हालांकि सर्वेक्षण में लोगों के स्वास्थ्य और पोषाहार स्तर पर विकास कार्यक्रमों के प्रभाव की जांच की जानी थी लेकिन जांच शरीर के वजन तथा ऊंचाई तक ही सीमित रह गई। इस सर्वेक्षण में ऐसे प्रश्नों जैसे क्या विद्यमान खून और विटामिन की कमी को दूर करने में भी सुधार हुआ था एवं क्या अस्वस्थता दर और शिशु मृत्यु दर में परिवर्तन हुआ है, का उत्तर नहीं मिल सका । इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में सफलता नहीं मिली है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

2811. **श्री राम जेठमलानी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अनेकों बड़े औद्योगिक घरानों ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु अनेकों परियोजनाएं सरकार के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस-किस बड़े औद्योगिक घरानों ने कौन-कौन सी परियोजनाएं सरकार को अगस्त, 1988 तक भेजी हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने के समय इस क्षेत्र में कार्यरत लघु उद्योगों के हितों के संरक्षण का ध्यान रखेगी, यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) मैसर्स जुआरी एग्रो केमिकल्स लि., गोआ ने हिमाचल प्रदेश में स्थित सिरमौर जिले में खुंगी, शतावर आदि की खेती करने और वहां प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । यह 100% निर्यात-उन्मुख यूनिट होगा और इस प्रस्ताव में मैसर्स पिल्लसबरी कम्पनी, संयुक्त राज्य अमेरीका के साथ विदेशी सहयोग अन्तर्ग्रस्त है ।

(ग) सरकार की नीति हमेशा यथा-वश्यक लघु उद्योगों के लिए कुछ वस्तुएं आरक्षित कर इनके हितों की सुरक्षा करने की रही है ।

बंधुआ मजदूरों को सहायता

2812. **श्री राम जेठमलानी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने से लेकर उन्हें पूर्ण रूप से बसाने के बीच की अवधि के दौरान उन्हें जीवनयापन हेतु सहायता देने की कोई योजना बनायी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ख) मजदूरों को बंधुआ बनाकर रखने के आरोप में गत तीन वर्षों के दौरान अलग अलग वर्ष में कितने लोगों को पकड़ा गया और कितनों को दंड दिया गया ?